

'Delhi-NCR to generate 1.5 lakh tonnes of e-waste by 2020'

Assocham finds 25% rise annually

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, January 9

Delhi-National Capital Region (NCR) is likely to generate about 1,50,000 tonnes of e-waste a year by 2020 from the current level of 85,000 tonnes, according to industry body Assocham.

E-waste is expected to be generated at compounded annual growth rate (CAGR) of about 25 per cent in the Delhi-NCR region, the industry/body said.

Growing problem

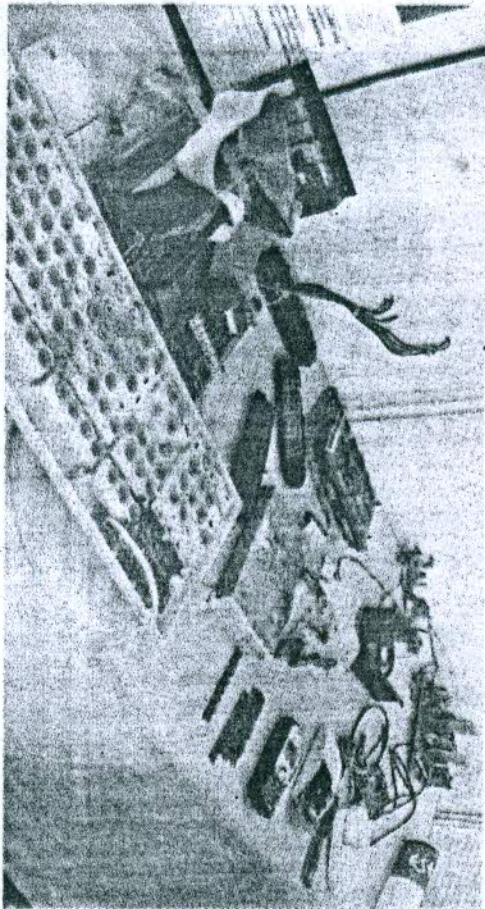
The Chamber cited factors such as low organised recycling, cross-border flow of waste equipment into the country, limited awareness regarding disposal, and lack of coordination between various agencies

for non-involvement of municipalities in e-waste management.

"Less than 15 per cent of India's electronic waste gets recycled in the absence of proper infrastructure, legislation and framework. The country produced approximately 2.5 million tonnes of e-waste in 2017," Assocham said.

The e-waste products have components that contain toxic substances such as lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, plastic, PVC (polyvinyl chloride), BFRs (prominated flame retardants), barium, beryllium, and carcinogens such as carbon black and heavy metals.

"Looking at the country-wise share in India's e-waste imports, the US has the maximum share of around 42 per cent and China at around 30 per cent, followed by Europe at around 18



less than 15 per cent of India's electronic waste gets recycled in the absence of proper infrastructure, legislation and framework

per cent and the remaining 10 per cent from countries like Taiwan, South Korea, Japan etc," Assocham said in a statement. Computer equipment ac-

counts for almost 68 per cent of e-waste, followed by telecommunication equipment (12 per cent), electrical equipment (8 per cent) and medical equip-

ment (7 per cent). Other equipment, including household e-scrap, accounts for the remaining 5 per cent, the Chamber said.

It said that as many as 12,500 mobile handsets, 8,500 TV sets and 5,500 personal computers are dismantled in the city every day for re-use of their component parts and materials as these products are getting more affordable.

Unused junk

E-waste typically includes discarded computer monitors, motherboards, cathode ray tubes, printed circuit board, mobile phones and chargers, compact discs, headphones, white goods such as liquid crystal display/plasma televisions, air-conditioners, and refrigerators, among others.

"With increasing use of these in our everyday life, e-waste is also piling up. Almost half of all unused and end-of-life electronic products lie idle in landfills, junkyards and warehouses," the Chamber said.

'NCR to spawn 1.5 lakh MT e-waste by 2020'

● AGENCIES/Delhi

The National Capital Region (NCR) is likely to generate about 1,50,000 metric tonnes (MT) of electronic-waste per annum by 2020, from the current level of 85,000MT, according to industry body The Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM). Electronic waste is expected to be generated at a compounded annual growth rate (CAGR) of about 25 per cent in the Delhi-NCR region, the industry lobby said on Tuesday.

ASSOCHAM attributed factors like low organised recycling, cross-border flow of waste equipment into the country, limited awareness regarding disposal and a lack of coordination between various authorities for non-involvement of municipalities in e-waste management. "Less than 1.5 per cent of India's total electronic waste gets recycled due to absence of proper infrastructure, legislation and framework. The country produced approximately 2.5 million metric tonnes of e-waste in 2017," ASSOCHAM

said. E-waste products have components that contain toxic substances like lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, plastic, polyvinyl chloride (PVC), brominated flame retardants (BFR), barium, beryllium, and carcinogens like carbon black and heavy metals. This deadly mix can trigger severe health problems in those handling the waste.

"Looking at the country-wise share in In-

dia's e-waste imports, US has a maximum share of around 42 per cent, China at around 30 per cent followed by Europe at around 18 per cent and the remaining 10 per cent is from other countries like Taiwan, South Korea, Japan etc," ASSOCHAM said in a statement.

A mixed bag

Computer equipment accounts for almost 68 per cent of electronic waste followed by telecom equipment (12 per cent), electrical equipment (eight per cent) and medical equipment (seven per cent). Other equipment, including household e-scrap, accounts for the remaining five per cent, the chamber said. It said that as many as 12,500 mobile handsets, 8,500 television sets and 5,500 personal computers are dismantled in the city every day for re-use of their component parts and materials as these products are getting more affordable and more and more people are using them.

Electronic waste typically includes discarded computer monitors, motherboards, cathode ray tubes, print-

ed circuit board, mobile phones and chargers, compact discs, headphones, white goods such as liquid crystal display / plasma televisions, air conditioners, refrigerators, among others. "With the increasing use of these [products] in our everyday life, e-waste is also piling up. Almost half of all unused and end-of-life electronic products lie idle in landfills, junkyards and warehouses," the chamber added.



ed circuit board, mobile phones and chargers, compact discs, headphones, white goods such as liquid crystal display / plasma televisions, air conditioners, refrigerators, among others. "With the increasing use of these [products] in our everyday life, e-waste is also piling up. Almost half of all unused and end-of-life electronic products lie idle in landfills, junkyards and warehouses," the chamber added.

दिल्ली-एनसीआर में पैदा होगा 1.50 लाख टन ई-कचरा

■ नई दिल्ली (भाषा)।

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वर्ष 2020 तक सालाना डेढ़ लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होने लगेगा। वर्तमान में यह मात्रा 85 हजार टन सालाना तक है। उद्योग मंडल एसोचैम ने यह आकलन जारी किया है।

उद्योग मंडल ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ई-कचरा साल दर साल 25 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। ई-कचरा में इस तेज रफ्तार से वृद्धि के लिए उद्योग मंडल ने संगठित

क्षेत्र में इसका निम्न स्तर पर पुनर्व्यवस्था, देश में बाहर से पुराने बेकार उपकरणों का तेजी से प्रवाह होना, इसके निपटान के बारे में कम जागरूकता और ई-कचरे के प्रबंधन को लेकर नगर निगम के स्तर पर विभिन्न निकायों के बीच समन्वय की कमी से यह स्थिति बनी है।

एसोचैम का कहना है कि इस समय देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का 1.5 प्रतिशत से भी कम को फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बेहतर सुविधाओं की कमी है,

■ मौजूदा समय में सालाना निकल रहा है 85 लाख टन कचरा

■ क्षेत्र में हर साल 25 फीसद की दर से बढ़ रहा है ई कचरा

■ डेढ़ फीसद से कम ई कचरे की हो पाती है रिसाइकिलिंग

■ ई कचरे में 68 फीसद हिस्सा कंप्यूटर व इससे जुड़े उपकरणों का

इसके लिए जरूरी कानूनी ढांचा और प्रारूप भी मौजूद नहीं है। वर्ष 2017 में देश में कुल मिलाकर 25 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ।

उद्योग मंडल ने कहा है कि ई-कचरे में कई तरह के हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कचरे में सीसा, कैडमियम, मर्करी, हैक्सावैलेंट क्रोमियम, प्लास्टिक, पीवीसी, बीएफआर, बेरियम और कार्बन ब्लैक और भारी धातु जैसे कई हानिकारक तत्व निकलते हैं। इनका कचरे में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा

असर पड़ सकता है। एसोचैम की विज्ञप्ति के अनुसार, भारत में आयात होने वाले कुल ई-कचरे में सबसे ज्यादा 42 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका से होता है। इसके बाद 30 प्रतिशत ऐसा आयात चीन से होता है, उसके बाद 18 प्रतिशत यूरोप और शेष 10 प्रतिशत हिस्सा ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों से आयात किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक कचरे में सबसे ज्यादा 68 प्रतिशत हिस्सा कंप्यूटर उपकरणों का होता है। इसके बाद 12 प्रतिशत दूरसंचार उपकरण शामिल हैं।

दिल्ली- एनसीआर में 2020 तक 1.50 लाख टन ई-अपशिष्ट पैदा होगा: एसोचैम

एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वर्ष 2020 तक सालाना डेढ़ लाख टन इलेक्ट्रॉनिक-कचरा पैदा होने लगेगा। वर्तमान में यह मात्रा 85 हजार टन सालाना तक है। उद्योग मंडल एसोचैम ने यह आकलन जारी किया है।

उद्योग मंडल ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ई-कचरा साल दर साल 25 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। ई-कचरा में इस तेज रफ्तार से वृद्धि के लिए उद्योग मंडल ने संगठित क्षेत्र में इसका निम्न स्तर पर पुनर्चक्रण, देश में बाहर से पुराने बेकार उपकरणों का तेजी से प्रवाह होना, इसके निपटान के बारे में कम जागरूकता और ई-कचरे के प्रबंधन को लेकर नगर निगम के स्तर पर विभिन्न निकायों के बीच समन्वय की कमी से यह स्थिति बनी है।

एसोचैम का कहना है कि इस समय देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का 1.5-प्रतिशत से भी कम को फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बेहतर सुविधाओं की कमी है,



इसके लिए जरूरी कानूनी ढांचा और प्रारूप भी मौजूद नहीं है। वर्ष 2017 में देश में कुल मिलाकर 25 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ।

उद्योग मंडल ने कहा है कि ई-कचरे में कई तरह के हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कचरे में सीसा, कैडमियम, मर्करी, हैक्सावैलेंट क्रोमियम, प्लास्टिक, पीवीसी, बीएफआर, बेरियम और कार्बन ब्लैक और भारी धातु जैसे कई हानिकारक तत्व निकलते हैं। इनका कचरे में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

एसोचैम की विज्ञप्ति के अनुसार, भारत में आयात होने वाले कुल ई-कचरे में सबसे ज्यादा 42 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका से होता है। इसके बाद 30 प्रतिशत ऐसा आयात चीन से होता है, उसके बाद 18

प्रतिशत यूरोप और शेष 10 प्रतिशत हिस्सा ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों से आयात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में सबसे ज्यादा 68 प्रतिशत हिस्सा कंप्यूटर उपकरणों का होता है। इसके बाद 12 प्रतिशत दूरसंचार उपकरण शामिल हैं। आठ प्रतिशत इलैक्ट्रिकल और सात प्रतिशत चिकित्सा उपकरणों की हिस्सेदारी है। शेष पांच प्रतिशत उपकरण घरेलू इस्तेमाल के होते हैं।

एसोचैम ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में योजना 12,500 मोबाइल फोन, 8,500 टीवी सेट और 5,500 पर्सनल कंप्यूटरों को उनके उपकरणों को फिर से काम में लाने के लिए तोड़ा जाता है। इस तरह के उपकरणों को इस्तेमाल में लाने से वह सस्ते होते हैं और ज्यादा लोग उनका इस्तेमाल कर पाते हैं।

